भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 39

दिनांक 06 **फरवरी**, 2023

रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी

39# **श्री राम नाथ ठाकुर**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में रसोई गैस के सिलेंडर की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस के सिलेंडर पर दी जाने वाली राज सहायता को समाप्त करने से सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है कि रसोई गैस के सिलेंडर से राज सहायता को समाप्त करने से गरीब उपभोक्ता गैस सिलेंडर कम बार भरवा रहे हैं और वे भोजन बनाने के पुराने तरीके अपनाने के लिए बाध्य हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

(**श्री हरदीप सिंह पुरी**)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी' के संबंध में संसद सदस्य श्री राम नाथ ठाकुर द्वारा दिनांक 06.02.2023 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 39 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): देश में एलपीजी सहित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्य से जुड़े हुए हैं। तथापि, सरकार घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती-बढ़ाती रहती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को घरेलू एलपीजी की बिक्री पर काफी हानि हुई है। इस हानि की भरपाई करने के लिए सरकार ने हाल ही में ओएमसीज़ को 22,000 करोड़ रु. का एकबारगी मुआवजा अनुमोदित किया है।

दिल्ली में वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर का औसत आरएसपी क्रमशः 688 रुपए, 650 रुपए और 867 रुपए था। अन्य राज्यों की स्थिति में, एलपीजी के लिए आरएसपीज में अंतर का मुख्य कारण पत्तनों और बॉटलिंग संयंत्रों के बीच की दूरी और इसके परिणामस्वरूप एलपीजी की परिवहन लागत होती है। औसत सऊदी सीपी मूल्यों, जिस पर एलपीजी के मूल्य आधारित होते हैं, में इन वित्त वर्षों के दौरान 454 यूएस डॉलर/एमटी से लेकर 693 यूएस डॉलर/एमटी तक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 के दौरान औसत सऊदी सीपी का मूल्य और बढ़कर 710 यूएस डॉलर/एमटी हो गया है।

गरीब परिवारों की महिला सदस्यों को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी जिसके तहत बगैर जमानत राशि के 8 करोड़ कनेक्शन दिए गए थे। उज्ज्वला 2.0 के तहत सभी पीएमयूवाई लाभार्थियों को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शनों के अलावा निःशुल्क पहली रीफिल और स्टोव उपलब्ध करवाया जाता है। दिनांक 01.02.2023 की स्थिति के अनुसार उज्ज्वला 2.0 के तहत 1.6 करोड़ कनेक्शन जारी किए गए हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों के लाभ के लिए की गई पहल के रूप में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेमी) के तहत सरकार ने दिनांक 01.04.2020 से उज्ज्वला लाभार्थियों को अधिकतम 3 (तीन) निःशुल्क एलपीजी रीफिल उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना की घोषणा की थी। ओएमसीज ने एलपीजी रीफिल खरीदने के लिए पीएमयूवाई लाभार्थियों के बैंक खातों में 9670.41 करोड़ रुपए अंतरित किए हैं और इस योजना के तहत पीएमयूवाई लाभार्थियों ने 14.17 करोड़ रीफिल प्राप्त किए हैं।

पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी के इस्तेमाल को और अधिक बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मई 2022 से पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को एक वर्ष में अधिकतम 12 रीफिल तक 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. रीफिल की अतिरिक्त निर्धारित राजसहायता शुरू की है।

यह देखा गया है कि पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा ली गई रीफिलों की संख्या वर्ष 2018-19 में 15.99 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 31.26 करोड़ हो गई है और इसी अवधि के दौरान प्रति लाभाथ खपत 3.00 रीफिल (14.2 कि.ग्रा.) से बढ़कर 3.68 रीफिल (14.2 कि.ग्रा.) हो गई है।

****